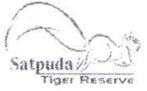


# कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133

E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in



क्रमांक/मा0चि0/ 3270

नर्मदापुरम, दिनांक 11/04/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक  
(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय:- diversion of 339.80 ha. Of forest land under Forest (conservation) Act, 1980, for relocation of village Suplai from Bori Sanctuary under Sarpura Tiger Reserve District (Hoshangabad) Narmadapuram, Madhya Pradesh State (Online No. FM/MP/FVC/145866/2021) reg.

संदर्भ:- 1. भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण डिवीजन) नईदिल्ली का ज्ञाप क्रमांक/8-23/2021-एफ.सी. दिनांक 08 अप्रैल 2022  
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ -5/1055/2021 /10-11/1277 दिनांक 08.04.2022

---0000---

विषयांतर्गत निवेदन है कि, भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण डिवीजन) नईदिल्ली द्वारा संदर्भित ज्ञाप से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई को परिक्षेत्र इटारसी के कक्ष क्रमांक पी एफ-174 एवं 179 एवं सोहागपुर के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-273 एवं आर.एफ.-225 में विस्थापित/पुनर्वास किए जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत 339.80 हेक्टे. में वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु भेजे गये प्रस्ताव में प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

i.	The State Govt. will submit the documentary evidence/relevant record indicating that an area of 260 ha is under occupation by way of Nistar/Community Rights;	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम सुपलई की वर्ष 1997 में वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक ईको विकास समिति हेतु सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार की गई जिसमें आवर्ती चराई हेतु कुल 1552.35 हेक्ट. भूमि समिति को आवंटित की गई थी जो योजना के पेज क्र. 67 एवं 68 पर उल्लेखित है पेज की सत्यापित प्रति एवं अधीक्षक, बोरी अभ्यारण्य इटारसी का पत्र परिशिष्ट-01 (पेज क्र. 01 से 05) पर संलग्न है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम सुपलई के विस्थापन उपरांत कुल 418.00 हेक्ट. वनभूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम सुपलई का क्षेत्रफल 158.00 हेक्ट. एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली उपरोक्त 1552.35 हेक्ट. में 260.00 हेक्ट. क्षेत्र शामिल है।
ii.	The State Govt. shall submit a written confirmation that the Village Suplai is within the core of Bori Wildlife sanctuary;	वनग्राम सुपलई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य में कोर जोन स्थित है। बोरी अभ्यारण्य का मानचित्र परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

निमित्त  
२

iii.	State Government shall submit the certificate of compliance under FRA, in both the areas i.e. the area being vacated and the area where the people will be relocated;	क्र.	विस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम/टोला का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
		1.	सुपलई भाग-01	पी.-174	110.00
		2.	सुपलई भाग-02	पी.-179	50.00
		3.	सुपलई भाग-03	आर.एफ.-225	100.00
		4.	सुपलई भाग-04	पी.-273	79.80
योग				339.80	
वनग्राम सुपलई के सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) से विस्थापन/पुनर्वास हेतु प्रस्तावित उपरोक्त स्थलों का एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र परिशिष्ट-3 (A,B,C एवं D) पर संलग्न है। वनग्राम सुपलई के विस्थापन /पुनर्वास उपरांत रिक्त वनभूमि का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।					
iv.	The correct and complete KML file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details;	डायवर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की KML file ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड की गई है। KML file परिशिष्ट-05 (A,B,C एवं D) पर संलग्न है।			
v.	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	पालन प्रतिवेदन ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ). पर अपलोड की गई है।			

B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:

i.	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the State in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी. (सी.) 202/95 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2019 को आई.ए. नं. 3924 और मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 20.05.2019 के अनुसार डायवर्ट होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।
ii.	The State Government shall ensure that the area under the Suplai Village becomes inviolate and no families are left within this village for further relocation. The 418.00 ha area to be made available as inviolate on account of relocation of village Suplai will be used for Wildlife conservation;	वनग्राम सुपलई के समस्त ग्रामीणों का पूर्ण रूप से विस्थापन किया जावेगा। ग्राम विस्थापन उपरांत रिक्त वनक्षेत्र इनवैलेट के रूप में रहेगा। विस्थापन उपरांत कोई भी व्यक्ति वहाँ पर शेष/निवासरत नहीं रहेगा। वनग्राम सुपलई के विस्थापन उपरांत रिक्त वनक्षेत्र 418.00 हेक्ट. वनभूमि को टाइगर कंजर्वेशन प्लान के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र के रूप में तैयार किया जावेगा।
iii.	State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are relocated do not return to the area;	शर्त का पालन किया जावेगा।
iv.	The Forest Department should encourage rehabilitated families in relocated forest area for improvement of their livelihood based on tree/ forest	शर्त का पालन किया जावेगा।

	based economic opportunities by providing appropriate training and imparting skillsets in ecotourism, Bamboo and Medicinal plants and other NTFPs through sustainable collection, processing, value addition and marketing etc. to help in conservation of forest area around rehabilitation;	
v.	The State Government shall ensure that further diversions of forest land in the tiger corridor of Satpura Tiger reserve for any upcoming developmental project should be curtailed as much as possible or appropriately mitigated with green infrastructures;	शर्त का पालन किया जावेगा।
vi.	The State Govt shall ensure that the resettled village should be fenced off as an enclosure on the forest side so as to prevent its further expansion and minimize human wildlife interfaces;	वन सीमा की तरफ फेंसिंग किया जावेगा।
vii.	The area to be vacated shall be mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian Forest Act, 1927, or the State Forest Act as the case may be;	वनग्राम सुपलई के विस्थापनउपरांत रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही Central Provinces Gazette में जारी अधिसूचना क्रमांक / 917 दिनांक 21.02.1879 से भारतीय वनअधिनियम 1878 की धारा 34 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम सुपलई का क्षेत्रफल मालनी ब्लॉक में शामिल है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-06 पर संलग्न है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के टाइगर कंजर्वेशन प्लान वर्ष 2008-09 से 2017-18 के Annexure-48 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ट-07 पर संलग्न है। साथ ही यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं उक्त अधिसूचना में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
viii.	The State Government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of Village will be developed as per approved Wildlife Management Plan/NTCA Guidelines;	शर्त का पालन किया जावेगा।
ix.	The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in this regard;	शर्त का पालन किया जावेगा।
x.	The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xi.	The State Govt. shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action compliance in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;	शर्त का पालन किया जावेगा।

xii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	किसी भी तरह का लेबर कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
xiii.	The State Govt. shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government / public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़को के किनारे/ स्कूल/प्रस्तावित ग्राम के बाउन्ड्री के आसपास/ आवासीय क्षेत्र के आसपास/ अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यवर्तित वनभूमि पर खड़े फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा।
xiv.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department;	व्यवर्तित वनभूमि में खड़े फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमण्डल (सा.) नर्मदापुरम, वनविभाग द्वारा किया जाता है।
xv.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvi.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xvii.	The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to the villagers being rehabilitated;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xviii.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xix.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year,	शर्त का पालन किया जावेगा।
xx.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का पालन किया जावेगा।
xxi.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court	शर्त का पालन किया जावेगा।

	Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	
xxii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त का पालन किया जावेगा।

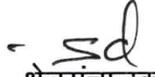
भारत शासन द्वारा वनग्राम सुपलई के विस्थापन/पुनर्वास हेतु संदर्भित पत्र से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है कृपया प्रकरण में अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध है।

(एल.कृष्णमूर्ति)  
भा.व.से.

क्षेत्रसंचालक  
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व  
नर्मदापुरम्  
नर्मदापुरम्, दिनांक .....

पृष्ठां.क्रमांक/मा.चि./ .....

- प्रतिलिपि:-
1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) नर्मदापुरम् वृत्त, नर्मदापुरम् की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
  2. वन मण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल नर्मदापुरम् की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

  
क्षेत्रसंचालक  
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व  
नर्मदापुरम्

## कार्यालय, अधीक्षक बोरी अभ्यारण्य, इटारसी

Ph:- 07572 -230016

email : - aditarsi.str@mp.gov.in

क्रमांक / 1062

दिनांक / 08.04.2022

प्रति,

श्रीमान क्षेत्र संचालक महोदय  
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम

विषय:- वनग्राम सुपलई की सूक्ष्म प्रबंध योजना प्रेषित करने बावत।

संदर्भ:- आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार।

विषयांतर्गत निवेदन है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम सुपलई के इको विकास समिति सुपलई की सूक्ष्म प्रबंध योजना की सत्यापित प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। वनग्राम सुपलई की सूक्ष्म प्रबंध योजना वर्तमान में भी लागू है। वनग्राम सुपलई के ग्रामीणों की पशु चराई, सूक्ष्म प्रबंध योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- सूक्ष्म प्रबंध योजना इको विकास समिति सुपलई सत्यापित प्रति

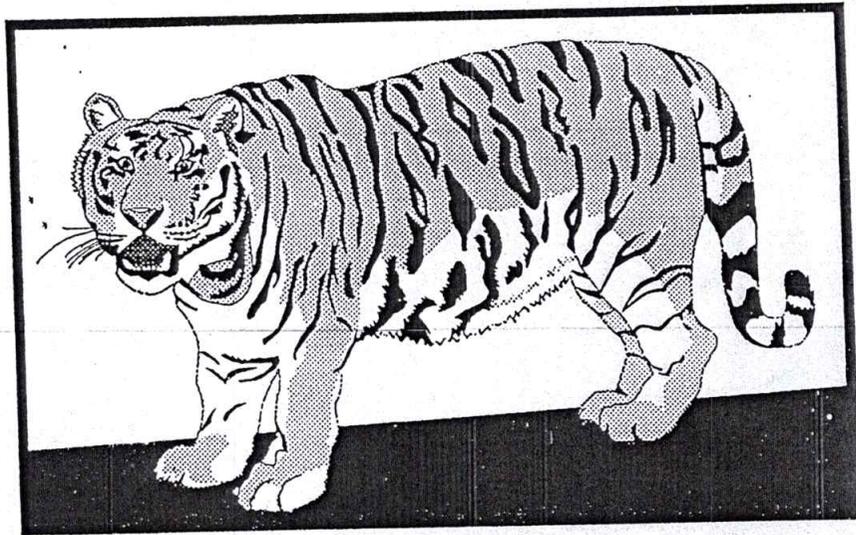
अधीक्षक  
बोरी अभ्यारण्य इटारसी

सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढी

बोरी अभ्यारण्य  
सूक्ष्म प्रबंध योजना

(वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक)

इको विकास समिति - सुपलई



वनमंडल :

सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढी

वन सुरक्षा  
(Forest Protection)

सुपलई ग्राम वन ग्राम है जो कि वन क्षेत्र मं: 170, 171 के पास स्थिति है। यह ग्राम आन्ध्रप्रदेश के सीमा के भीतर स्थिति है।

इको बिकास समिति सुपलई को वनसुरक्षा की दृष्टि से गैम रेन्ज भौरा के निम्न लिखित कम्पार्टमेन्ट वन सुरक्षा करने के लिये, आवंटित किये गये है।

1. कम्पा. 170	-	311.60 हेक्ट.
2. कम्पा 171	-	246.40 हेक्ट.
3. कम्पा 172	-	283.60 हेक्ट.
4. कम्पा 173	-	423.70 हेक्ट
5. कम्पा. 169	-	256.97 हेक्ट
	-	
	-	
कुल कम्पार्टमेन्ट 5	कुल -	1552.35 हेक्ट

उक्त कम्पार्टमेन्ट सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से दिए गये है। इनमें समिति का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहेगा एवं न ही इसका कोई लाभांश दिया जावेगा समिति सदस्य गस्ती करके अवैध कटाई अवैध शिकार घटना को रोकेंगे एवं यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसको पकड़वाने में पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसे प्रकरण पकड़ने के लिये समिति को भी अधिकार दिये गए है।

आन्ध्रप्रदेश की सुरक्षा करने पर अम्मा के प्रबन्धक ग्राम का इको बिकास कार्य करने में सहायता करेंगे। प्रतिबर्ष इको बिकास समिति सुपलई को अग्नि सुरक्षा करने का दायित्व भी दिया गया है। अग्नि सुरक्षा कार्य के लिये सुपलई बीट के कम्पार्टमेंट 169, 170, 171, 172, 173

कम्पार्टमेंट प्रदान किये जा रहे हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 1552.35 हेक्ट. है।

उक्त क्षेत्र में वनसुरक्षा समिति/इको विकास समिति पट्टन अग्नि सुरक्षा कार्य करेगी।

सत्यापित

अधीक्षक बोरी आन्ध्रप्रदेश  
इटासो

सरवत  
अध्यक्ष

इको विकास समिति सुपलई

H. K. K. K.  
आरबेट परिक्षेत्राधिकारी भौरा

4

68

# आवर्ती चराई योजना

(Rotational Grazing)

1. समिति को आवंटित कुल क्षेत्र / कम्पार्टमेंट - 5 हेक्ट. 1552.35
2. आवर्ती चराई हेतु खुले क्षेत्र का विवरण

वर्ष	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
प्रथम वर्ष 98	169	256.97 हेक्ट.
द्वितीय वर्ष 99	170	311.60 हेक्ट.
तृतीय वर्ष 2000	171	276.40 हेक्ट.
चतुर्थ वर्ष 2001	172	283.68 हेक्ट.
पंचम वर्ष 2002	173	423.70 हेक्ट.
कुल -	5 कम्पार्टमेंट	1552.35 हेक्ट.

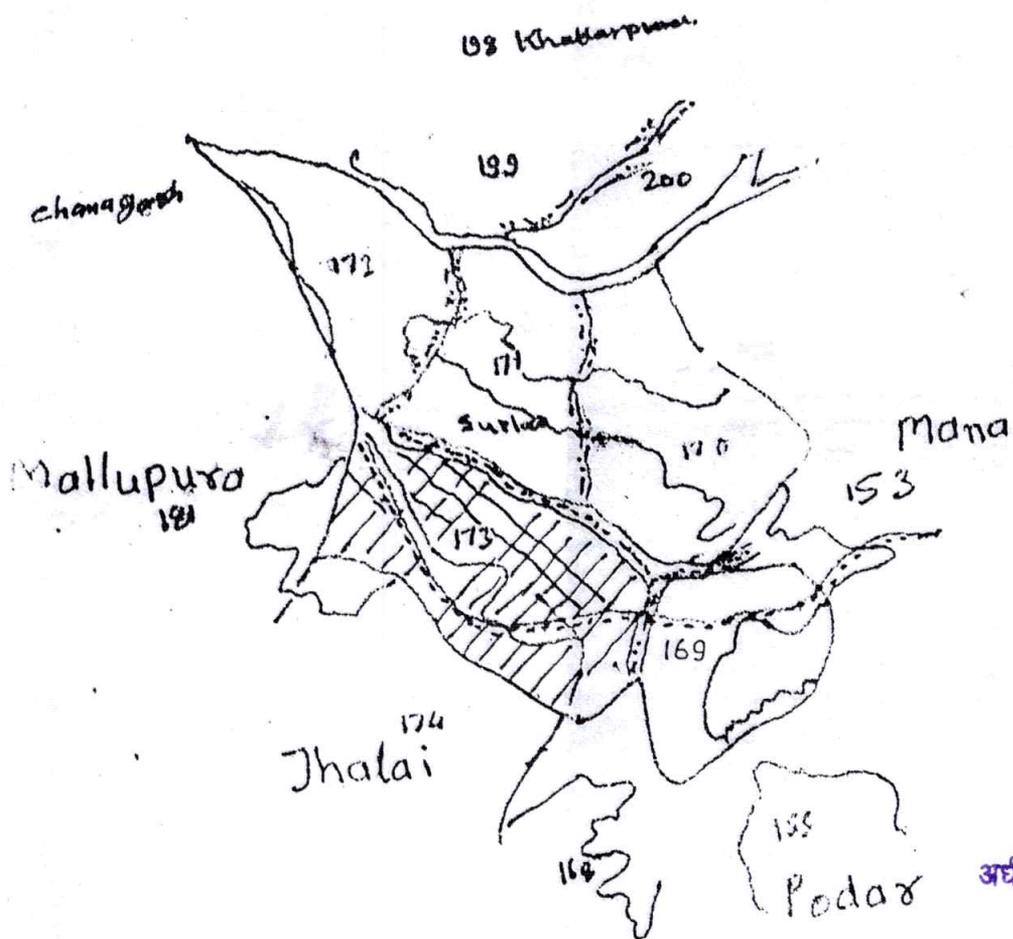
उक्त कक्षों को क्रम से प्रति वर्ष चराई हेतु खोला जावेगा, शेष कक्ष में चराई प्रतिबंधित रहेगी

सत्यापित

अधीक्षक वारी अम्बारण्य  
इटासी

*H. K. Singh*  
गेम परिक्षेत्र अधिकारी  
भौरा

# इको विकास समिति सुपलई सुरक्षा हेतु सौपा गया क्षेत्र



सत्यापित

W

अधीक्षक बोरी अभ्यारण्य  
इटारसी

सकंत

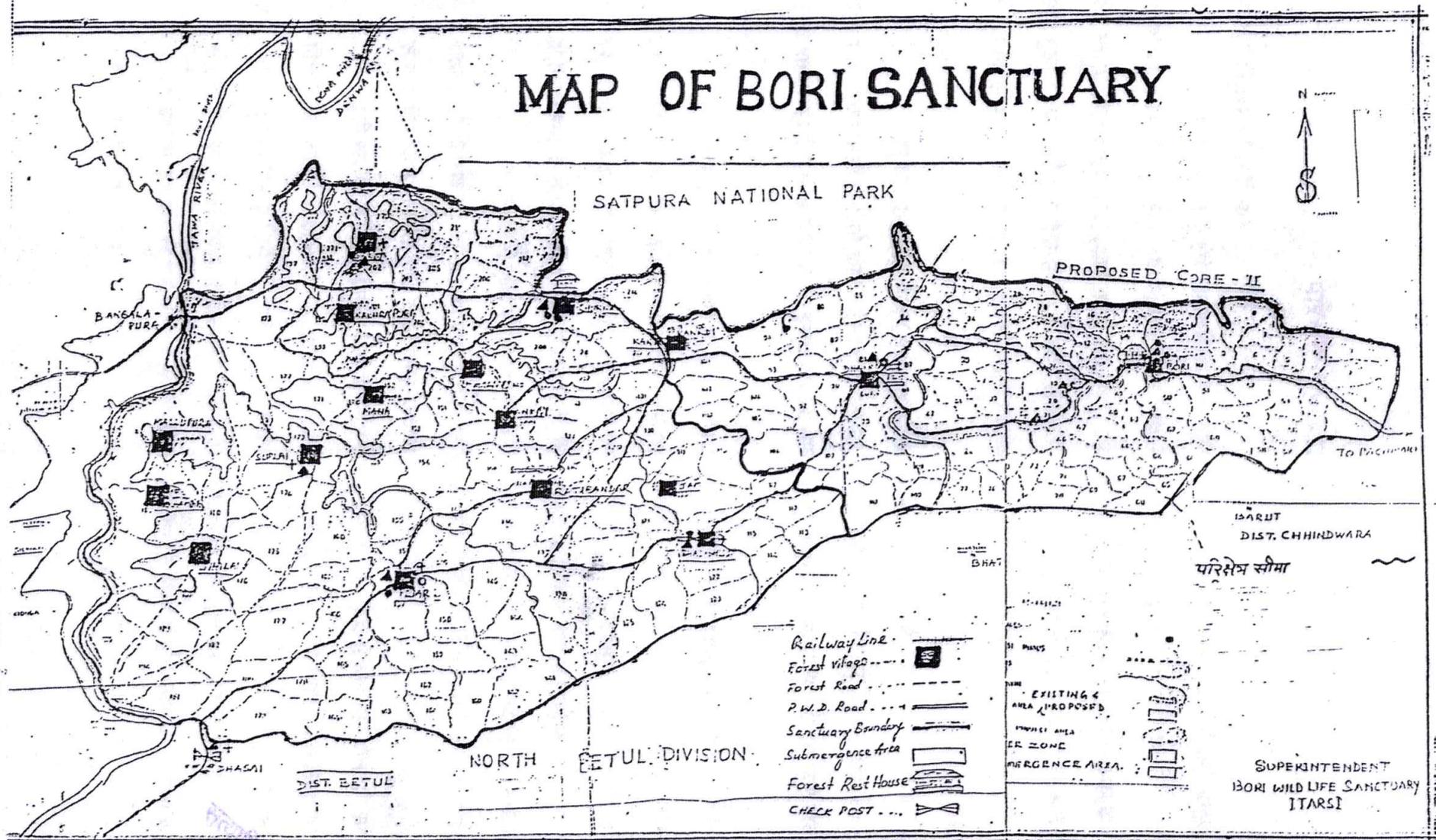
कक्ष की सीमा = - - - - -

नदी नाले =

कक्ष क्रमांक	रकबा हेक्ट.
169	256.97
170	311.60
171	246.40
172	283.60
173	423.70
<u>5</u>	<u>1552.35</u>

H. K. S. J.  
जैम परिक्षेत्र अधीक्षक  
भोपा

# MAP OF BORI SANCTUARY



- Railway Line
- Forest Village
- Forest Road
- P.W.D. Road
- Sanctuary Boundary
- Submergence Area
- Forest Rest House
- CHECK POST

ISARUT  
DIST. CHHINDWARA  
परिक्षेत्र सीमा

EXISTING & PROPOSED AREA

EMERGENCE AREA

SUPEKINTENDENT  
BORI WILD LIFE SANCTUARY  
(ITARS)

EDC Head Qr...

*H. K. K.*  
श्री परिक्षेत्र अधिकारी  
भोरा

परिक्षेत्र-2

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

District Level Forest Right Committee Dist. Hoshangabad (M.P.)

\*\*\*\*\*

No...12684

Date...11.10.2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

*(This Certificate is Issued on the basis of recommendation of sub-Division Level FRA Committee and the District Level FRA Committee.)*

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter NO. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 110.00 hectares of forest land proposed to be diverted in *Compartment No. RF-174* in favour of Forest Department for Rehabilitation of forest village Suplai Part-1 in Hoshangabad district falls within jurisdiction of Tangana village in Itarsi tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 110.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure-1 to annexure-3
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Tangana villages is enclosed as annexure-2 as above.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

NEERAJ (Neeraj Kumar Singh)  
Collector  
Hoshangabad

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

District Level Forest Right Committee Dist. Hoshangabad (M.P.)

\*\*\*\*\*

No...12686

Date...11.10.2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

*(This Certificate is Issued on the basis of recommendation of sub-Division Level FRA Committee and the District Level FRA Committee.)*

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter NO. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 50.00 hectares of forest land proposed to be diverted in *Compartment No. RF-179* in favour of Forest Department for Rehabilitation of forest village Suplai Part-2 in Hoshangabad district falls within jurisdiction of Tangana village in Itarsi tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 50.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure-1 to annexure-3
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Tangana villages is enclosed as annexure-2 as above.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

NIGRAJ (Niraj Kumar Singh)  
Collector  
Hoshangabad

## FORM-II

(for projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh

District Level Forest Right Committee Dist. Hoshangabad (M.P.)

\*\*\*\*\*

No. 12680

Date... 11.10.2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

*(This Certificate is Issued on the basis of recommendation of sub-Division Level FRA Committee and the District Level FRA Committee.)*

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter NO. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 100.00 hectares of forest land proposed to be diverted in *Compartment No. RF-225* in favour of Forest Department for Rehabilitation of forest village Suplai Part-3 in Hoshangabad district falls within jurisdiction of Bagra Tawa village in Babai tehsil. It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Committee(s), of Bagra Tawa Gram Sabha(s) Bagra Tawa are enclosed as annexure-1 to annexure-2
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bagra Tawa villages is enclosed as annexure-2 as above.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

(Neeraj Kumar Singh)  
Collector  
Hoshangabad

(D)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

District Level Forest Right Committee Dist. Hoshangabad (M.P.)

\*\*\*\*\*

No. 12682

Date...1.1.10.2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

*(This Certificate is Issued on the basis of recommendation of sub-Division Level FRA Committee and the District Level FRA Committee.)*

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter NO. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 79.8 hectares of forest land proposed to be diverted in *Compartment No. PF-273* in favour of Forest Department for Rehabilitation of forest village Suplai Part-4 in Hoshangabad district falls within jurisdiction of Patharai village in Sohagpur tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 79.80 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure-1 to annexure-3
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Patharai villages is enclosed as annexure-2 as above.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

(Neeraj Kumar Singh)  
Collector  
Hoshangabad

## FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

District Level Forest Right Committee Dist. Hoshangabad (M.P.)

\*\*\*\*\*

No. 2074

Date 14.02.2022

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter NO. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) in the Forest Village, Suplai in Bori Wildlife Sanctuary of Satpura Tiger Reserve, for 418.000 Ha of forest land(Comp,no173,Comp.no191part,comp.no192part and Comp.no174part)for Voluntary Village Relocation. It is further certified that,

- (a) The completed process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 418.000 hectares of forest area, proposed for Village Relocation .
- (b) The proposal for Village Relocation (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA has been carried out, and that they have given their consent to the proposed relocation and the compensation and ameliorative measures.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The Village Relocation process by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The Forest Village, Suplai Shall be voluntarily relocated and all the rights shall be settled as per the Voluntary Village Relocation Policy of the NTCA and Government of Madhya Pradesh.

(Neeraj Kumar Singh)

Collector

Hoshangabad

01/18/2015-5

# KML file of Suplai Part-2 (Com.no.-179 Area -50.00 Ha)



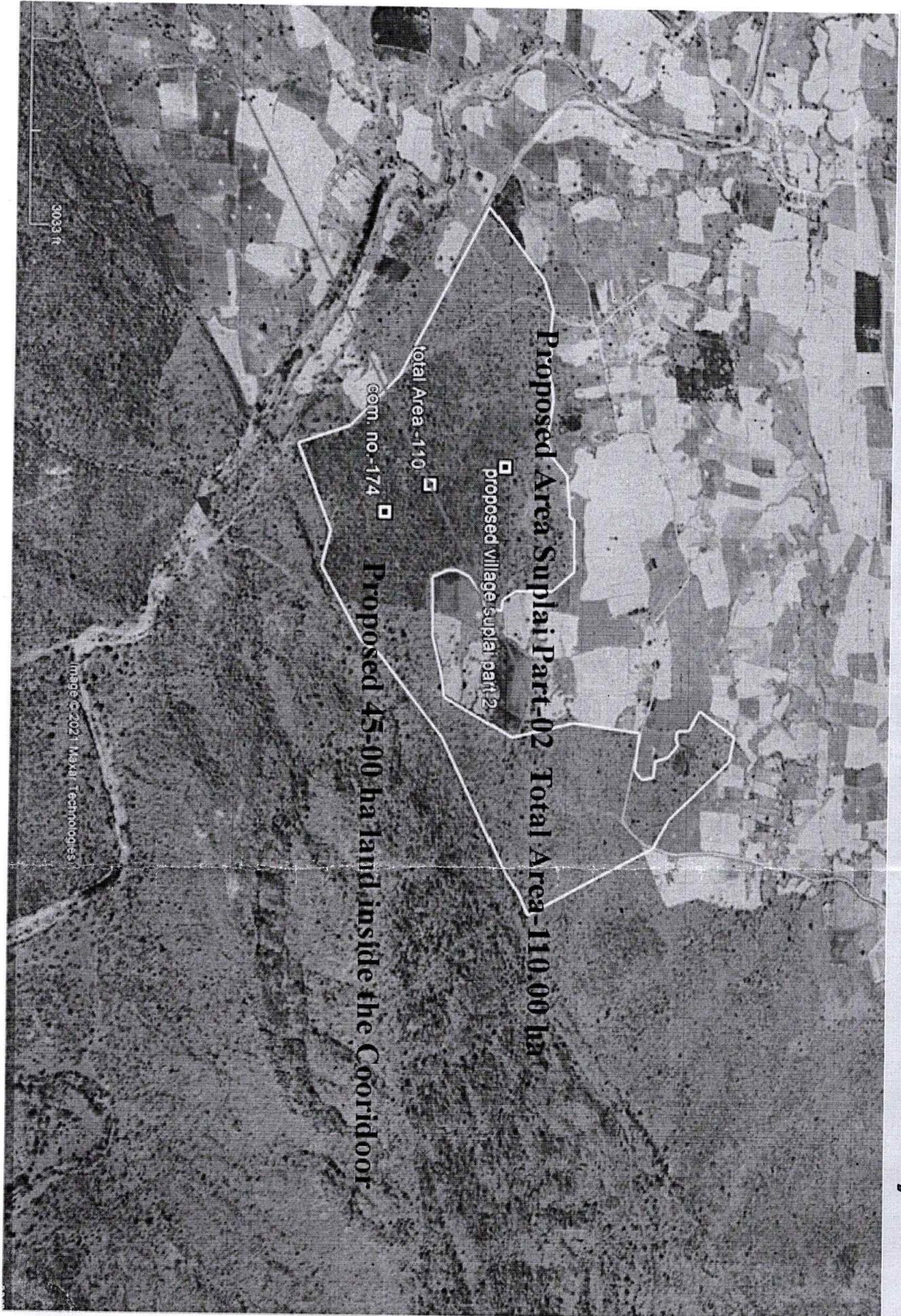


(C)

# KML file of Suplai Part -4 (Com.no.-273 Area -.79.80 Ha)



# KML file of Suplai -1(Com.no.-174 Area -110.00 Ha)





The  
**Central Provinces' Gazette.**

NAGPUR, SATURDAY, MARCH 1, 1879.

**PART IA.**

**Notifications by the Chief Commissioner, Central Provinces.**

*Dated Nagpur, the 24th February 1879.*

No. 917a.—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Indian Forest Act, 1878, the Chief Commissioner hereby declares the lands described in the Schedule hereto annexed to be reserved forests :—

District.	Pargana or other Sub-Division.	Name of Forest.	Description of boundaries.
WARDHA.	Ashti	1 Bharkumbha	Bounded on the north by private lands of mauza Bharkumbha; east and south-east by the private lands of mauza Vadial; south and south-west by the private lands of Bharkumbha; and west and north-west by the private lands of mauza Saonga.
		2 Sitarpur	Bounded on the north by the malguzari areas of mauzas Satarpur and Nagazira; east by the malguzari area of mauza Tamni and Government forest tract of mauza Zargaon; south by the Government forest tract of mauza Enora; south and west by the malguzari areas of mauzas Ghatsur and Rajapur; west by the Government forest tract of mauza Bharkumbha and malguzari area of Khanapur; and north-west by the Government forest tract of mauza Badata.
		3 Jhargaon	Bounded on the north by the private areas of Tamni and Zargaon; north-east by the malguzari area of mauza Tamni; east by the malguzari area of mauza Sahur; south-west by the malguzari area of mauza Panchala; south by the malguzari area of mauza Porgawban; south-west by the Government forest tract of mauza Enora; and west by the Government forest tract of mauza Satarpur.

No. 917h.—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Indian Forest Act of 1878, the Chief Commissioner hereby declares the lands described in the Schedule hereto annexed to be Reserved Forests :—

District.	Pargana or other Division.	Name of Forest.	Description of boundaries.
HOSHANGABAD.	Hoshangabad & Sobagpur Parganas.	No. 1, North Denwa ...	Bounded on the north by a cleared line beginning at trijunction pillar of Gogrimatta and Amadeh village lands and unreserved forest and running along the south boundaries of the following village lands up to the Tawa river, where the southern boundary of Kolgaon also joins in 1 Amadeh, 2 Mahdo, 3 Bari, 4 Dokrikhera, 5 Anhani, 6 Khursikhapa, 7 Mohari, 8 Kathnikhapa, 9 Sangai, 10 Chargon, 11 Gonadeh, 12 Gadi khiri, 13 Dondadhe, 14 Singwara, 15 Nibhora, 16 Paraswara, 17 Pathraie, 18 Dhamaniya, 19 Silkauth, 20 Gogri, 21 Dobb, 22 Khontiya, 23 Dularya, 24 Pehutala, 25 Mehdwari, 26 Gurariya, 27 Mohgaon, 28 Singpur, 22 Gujawara, 30 Kolgaon; east by a cleared line running along the west boundaries of the following villages up to trijunction pillar of Gogrimatta, Bingondi and Amadhe village lands, 1 Piswa, 2 Piparia, 3 Patni, 4 Khairi 5 Tekapar, 6 Bugondi, 7 Mohgaon; west by the River Tawa up to its junction with the Denwa river; south by the Denwa river up to where the Piswa village boundary joins in. Within the limits above defined are the private lands of (1) Karpathar, (2) Urdon and (3) Gogri, not included under the name of the Denwa forest.
	Sohagpur Pargana.	No. 2, South Denwa ...	Bounded on the north beginning on the Denwa river at a point half mile west of trijunction pillar of Bandakhera and Piswa village lands and running with the Denwa up to its junction with the Sombadra river; east by a cleared line along with western limits of the village lands of Harakap Taluka; west along the Sombadra river up to Bori reserve; south by the Pachmarhi range scarps, also north boundary of Bori reserve up to village lands of Rohi ghat. Within the above limits are the village lands of Magra and Sonepur, not included under the name of the South Denwa forest.
		No. 3, Malni ...	Bounded on the north by the Denwa river from the Sombadra to the Tawa rivers; east by the Sombadra river to its junction with the Denwa river; west by the Tawa river up to the Bhunkund stream; south along the joint boundaries of Betul and Hoshangabad district up to the Sombadra river. Within the above limits is the Ramkri grant of 100 acres, not included under the name of the Malni forest.
	Hoshangabad Pargana.	No. 4, Rampura Amoda.	Bounded on the north by a cleared land beginning on the Tawa river below Kotra village and running with the village lands of Kotra Batkoi; east along the Tawa river up to Kotra village lands; west along the north boundary of Borda Taluka.

**Annexure - 48**  
**SATPURA TIGER RESERVE**  
 REVISED PROPOSAL FOR VILLAGE RELOCATION

Core zone Notificaton No. F-15-31-2007-X-2 dt 24-12-2007

SATPURA NATIONAL PARK																	
Village to be Retained						Village to be Excised						Village to be Relocated					
Name	Type	Area Hact.	Popula-tion	Cattle	No. of Families	Name	Type	Area Hact.	Popula-tion	Cattle	No. of Families	Name	Type	Area Hact.	Popula-tion	Cattle	No. of Families Approx.
0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	(1)Ghoranar	Fv	131.910	111	88	32
												(2)Badkachhar	Rv	41.050	155	134	35
												(3)Pattan	Rv	47.790	238	219	60
												(4)Jambudweep	Rv	1.986	6	27	2
												(5)Kajari	Rv	14.629	162	89	43
												(6)Binora	Rv	61.697	200	148	48
												(7)Rorighat	Rv	214.891	234	112	72
												(8)Bariam(Part)	Rv	11.910	5	40	2
														525.863	1111	857	294

**BORI SANCTUARY**

Village to be Retained						Village to be Excised						Village to be Relocated					
Name	Type	Area Hact.	Popula-tion	Cattle	No. of Families	Name	Type	Area Hact.	Popula-tion	Cattle	No. of Families	Name	Type	Area Hact.	Popula-tion	Cattle	No. of Families Approx.
(1)Jhalai	Fv	493.330	299	832	53	0	0	0	0	0	0	(1)Bori	Fv	254.170	387	248	107
(2)Suplai	Fv	113.310	419	696	76							(2)Khakarapura	Fv	100.464	132	615	45
(3)Khamda	Fv	496.330	264	352	49							(3)Sakot	Fv	68.977	104	303	40
(4)Mallupura	Fv	565.440	154	531	27							(4)Kankari	Fv	17.194	138	209	42
												(5)Jam	Fv	220.140	272	392	66
												(6)Bharbhur	Fv	320.511	288	337	70
												(7)Sankai	Fv	214.088	383	416	90
												(8)Ratibandar	Fv	320.500	238	205	68
												(9)Churana	Fv	190.974	322	808	95
												(10)Mana	Fv	108.050	453	619	112
												(11)Malni	Fv	87.170	617	809	152
												(12)Podar	Fv	292.970	471	623	125
		1668.410	1136	2411	205									2195.208	3805	5584	1012